

स्टार समाचार, भोपाल

• 3 JAN 2015

नीति आयोग का गठन सही अर्थों में संघीय ढांचे की नींव

स्टार समाचार | भोपाल

भारत योजना आयोग की जगह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थापित किए गए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के गठन से भारत के रूपांतरण की विकास प्रक्रिया में सही अर्थों में संघीय ढांचे की नींव रखी गई है। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ब्लाग और ट्विटर में कहा कि यह आयोग भारत



की विकास संबंधी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में काफी मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनवरी 2015 की नई सुबह भारत ने सहकार और लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित विकास के नये युग में आँखें खोली हैं। यह युग प्रवर्तक परिवर्तन भारत योजना आयोग के स्थान पर बनाये गये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया के

रूप में आया है। वर्ष 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुँमुखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था, वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ठीक था। आजादी के बाद देश का जो विकास हुआ उसमें आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकास के नियोजन और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में योजना आयोग ने काफी हद तक अच्छा काम किया। लेकिन बीते कुछ दशक में, विशेष कर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व की प्रासंगिकता लगातार खत्म होती चली गई। लोकतंत्र में विभिन्न प्रदेश में अलग-अलग राजनैतिक दलों की सरकारें होती हैं। यह बात लगातार महसूस की जा रही थी कि केन्द्र में सत्ताधारी दल के राजनैतिक हितों के संवर्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनैतिक आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे।

आयोग की कार्य प्रणाली

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना आयोग की कार्य-प्रणाली में लोकतांत्रिक भावना का अभाव हो गया था। योजना निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा रस्मी हो गई थी। योजनाएं केन्द्र से बनाकर राज्यों को भेजी जा रही थीं। इनमें राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी कारण योजनाओं का वांछित लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने लगातार यह बात अनेक मंचों से कही कि जिस तरह हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती उसी तरह हर राज्य के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के विषय में यह बात ज्यादा लागू होती है।